



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2004/माघ 14, 1925

No. 31]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2004/MAGHA 14, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2004

सं. एफ. 2(53)-बी (डी)/2003.—निम्नलिखित सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

अंतरिम बजट 2004-2005

वित्त मंत्री

श्री जसवन्त सिंह का भाषण

3 फरवरी, 2004

I. प्रस्तावना

अध्यक्ष महोदय,

1. मैं राजकोषीय वर्ष 2004-05 के एक हिस्से के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके लिए लेखानुदान का अनुरोध किया जाता है ताकि सरकार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके और वर्ष 2004-05 के पहले चार महीनों के दौरान सभी अनिवार्य व्ययों को पूरा कर सके। परन्तु यहां प्रस्तुत अनुदान-मांगों और वार्षिक वित्तीय विवरण सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए हैं, यद्यपि जैसाकि ओमंतौर पर होता है नियमित बजट पेश करते समय इन्हें संशोधित किया जा सकता है। मैं वित्त विधेयक भी पेश कर रहा हूँ ताकि विद्यमान कर-संरचना को इस समय जारी रखा जा सके।

2. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार का लगातार सातवां बजट है। इस अवसर पर मैं देश एवं सदन के साथ हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर महान संतोष को भावना को व्यक्त करता हूँ और भारत की जनता के सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन के प्रति हमारा हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूँ जो उन्होंने एन.डी.ए. और इसकी सरकार को निरन्तर रूप से और खुले दिल से प्रदान किया। देश की वृहद-आर्थिक स्थिति आज काफी बेहतर है जो पिछले पचास वर्षों में कभी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इस बात को काफी अधिक और व्यापक मान्यता मिल रही है कि भारत राष्ट्रीय प्रयत्नों के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और इसने सुनिश्चित वृद्धि और अधिक राष्ट्रीय समृद्धि के साथ स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित कर ली है।

II. एन.डी.ए. : आर्थिक नीति - प्रयत्न एवं उपलब्धियां

3. सरकार ने नागरिकों के कल्याण को अपने उत्तरदायित्वों में निरन्तर शक्ति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हमारी "पांच-प्राथमिकताओं" का अनुपालन जारी है। हमारे नागरिकों के जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान रोजगार बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन, कृषि में दूसरी हरित क्रान्ति, आधार-संरचना का विकास, राजकोषीय मजबूती और विनिर्माण क्षेत्र की अधिक कार्यकुशलता के लक्ष्य हमारी हार्दिक वचनबद्धताएं हैं।

4. महोदय, हम इस बात को मानते हैं कि यह दोनों बातें आवश्यक हैं: भारत के पुनरुत्थान का दृष्टिकोण और साथ ही साथ एक जागृति जिससे हमारे देश के कमजोर वर्गों को गरीबी से मुक्त किया जा सके। हमारा मानना है कि आर्थिक विकास केवल अर्थशास्त्र के बारे में ही नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ हमेशा इसका एक राजनैतिक पहलू भी है क्योंकि जो 'विकास' संवेदना एवं सहानुभूति रहित हो वह यथार्थ रूप में विकास नहीं कहा जा सकता। वास्तव में वृद्धि के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं, वह अनिवार्य साधन हैं, परन्तु उन्हें ऐसे संकेतक होना चाहिए जो सभी के लिए न्याय प्रदान करने में हमारी मदद कर सकें। इसी कारण 'सकल-राष्ट्रीय संतोष' एक उत्प्रेरक की तरह महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रीय प्रयत्न बढ़ाने को प्रेरित करता है। राष्ट्रीय संतुष्टि एवं खुशहाली प्राप्त करने के लिए ही लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाए जाते हैं 'गरीब के पेट में दाना, गृहिणी की टुकिया में अन्ना'। महोदय, भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाना चाहिए और हम यह कह सकते हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय भविष्य है, देश के भविष्य निर्माण के लिए सेवा करना सरकार के लिए सम्मान की बात है और यह इसका परम कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय आर्थिक उद्देश्य इसी भावना से प्रेरित हैं।

5. अध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष में आर्थिक वृद्धि के संकेतक काफी उत्साहजनक हैं। मुद्रास्फीति की 4 से 4.5 प्रतिशत तक की दर के साथ, इस वर्ष हम यह आशा करते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5 और 8 प्रतिशत के बीच होगी। यद्यपि इस समय उच्च वृद्धि के अनुमान किए गए हैं परन्तु हम उपर्युक्त आंकड़ों से अधिक की बात अभी नहीं करना चाहते। वृद्धि का यह स्तर अत्यधिक संतोष का विषय है। महोदय, रोजगारों में बढ़ोतरी हुई है परन्तु इसी तरह लोगों की आशाएं भी बढ़ती गई हैं। हमें इस चुनौती का सामना करना चाहिए। आधार-संरचना में बड़े प्रयत्नों ने तुरंत रोजगार के अनेक स्तर पहले ही उत्पन्न किए हैं, साथ ही साथ संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों के व्यापक क्षेत्र में अतिरिक्त अच्छे रोजगारों की बुनियाद भी डाली गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। 19 दिसम्बर, 2003 को हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ने 100 बिलियन अमरीकी डालर का स्तर पार कर लिया था। इसमें वृद्धि जारी है और हमें कमी की मानसिकता से छुटकारा मिल रहा है। अधिक पारदर्शिता और नागरिकों के साथ आवश्यक सूचना की साझेदारी के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की पहली रिपोर्ट आज जारी की जा रही है। इसे मंत्रालय एवं आर.बी.आई. की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है।

6. महोदय, नियंत्रित मुद्रास्फीति, गिरती हुई ब्याज दरों और सुदृढ़ पूंजी बाजार के कारण हमारी अर्थव्यवस्था त्वरित वृद्धि की दिशा में चल रही है। इसे और आगे प्रोत्साहित करना हमारा उत्तरदायित्व है। अतः हमारी वृहद आर्थिक नीति के मूल सिद्धांतों के संरक्षण पर अधिक ध्यान देना होगा। अर्थव्यवस्था का प्रबंधन एक सतत उत्तरदायित्व है, प्रशासन न तो रुक सकता है न बन्द हो सकता है और पूर्ण सुदृढ़ीकरण तथा वृद्धि की गति निरंतर बढ़ाने के उपाय हमेशा समय पर ही किए जाने चाहिए। केवल इसी प्रकार से हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं जिसकी हम स्वतंत्रता के समय से ही कल्पना करते आ रहे हैं।

III. पहले एवं भावी योजना

सुधार उपाय

अंत्योदय अन्न योजना

7. प्रधानमंत्री द्वारा दिसम्बर, 2000 में चलाई गई अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत इस समय गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के 1.5 करोड़ परिवार शामिल हैं। यह एक अत्यधिक सफल कार्यक्रम है जिसकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई है। यह प्रत्यक्ष रूप से गरीबी का उपशमन करता है और पोषण संबंधी कमी दूर करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब 2 करोड़ बी.पी.एल. परिवारों को शामिल करके इसका विस्तार किया जा रहा है। ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके अंतर्गत जनजातीय राज्य, जिले या बेल्त्स को अधिक हिस्सा मिले। इसे 1 अप्रैल, 2004 से लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

8. गरीबी और बीमारियों का परस्पर संबंध है। निजी क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाओं वाले अस्पताल हमारे अनेक नागरिकों की पहुंच से बाहर हैं। अतः प्रधानमंत्री ने पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) की तरह सरकारी क्षेत्र में छः अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की थी। इस 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे छः नए अस्पतालों को बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में स्थापित किया जाएगा। माननीय सदस्यों को अवश्य ज्ञात होगा कि 1956 से किसी भी सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे किसी भी दूसरे अस्पताल की स्थापना नहीं की गई। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के इन छः राज्यों में प्रत्येक में एक-एक मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) के स्तर का बनाया जाएगा।

9. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन दोनों स्कीमों के लिए इस बजट में ही प्रावधान कर लिया गया है।

ग्रामीण

10. सरकार हमारे किसानों तथा ग्रामीण भारत में रह रहे अन्य नागरिकों को सुविधाजनक ढर्रे पर समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वचनबद्ध है। इस उद्देश्य हेतु, निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे:-

- जुलाई, 2003 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा फसल ऋण पर ब्याज की दर घटाकर 9 प्रतिशत करने की घोषणा की गई थी। नाबार्ड अधिधेयम में भी उपयुक्त संशोधन किया गया। मैं भारतीय बैंक संघ से आग्रह कर रहा हूँ कि कृषि उद्देश्यों हेतु ब्याज दरों में और कमी लाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने पहले ही ब्याज दरें घटा दी हैं। मुझे विश्वास है कि अन्य बैंक भी वर्तमान में मौजूद ऋणों की ब्याज दरों में कमी करेंगे।
- पारम्परिक रूप से बैंक कृषि पर ऋण प्रदान करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभूति मांगते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशि प्राप्त करने हेतु बैंक उधारकर्ता किसान पर संपूर्ण जोत को प्रतिभूति के रूप में बंधक रखने हेतु दबाव डालते हैं। इसलिए अब बैंकों को सलाह दी जा रही है कि वह किसान विशेष की ऋण क्षमता का मूल्यांकन करें और संपूर्ण जोत को बंधक रखकर उसके जरिए

अतिरिक्त संपादित प्रतिभूति हेतु दबाव न डालें। सैद्धांतिक तौर पर, संपादित प्रतिभूति ऋण के मूल्य के समानुपात में होनी चाहिए।

- **फसल ऋण खातों के मामले में अनर्जक परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवस्थाओं के निर्धारण से ऐसे किसानों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था में समस्याएं पैदा हुई हैं जहां कृषि आय की मौसम निर्भरता और अनिश्चितता को पूर्ण रूप से नहीं समझा गया है। डा. वी.एस. व्यास, जो एक प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक हैं, की अध्यक्षता में इस मुद्दे के समाधान हेतु एक समिति का गठन किया गया है। 90 दिनों के अंदर उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की जाएगी।**
- **मुझे विश्वास है कि सभी पात्र किसान 31 मार्च, 2004 तक अपना किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर लेंगे। ग्रामीण भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी विकास के लाभ प्रदान करने हेतु मौजूदा किसान क्रेडिट कार्डों को इसके बाद व्यक्तिगत अनुरोध पर ए.टी.एम. मशीनों पर उपयोग हेतु, जहां कहीं भी ऐसी सुविधा उपलब्ध है, संशोधित किया जाएगा।**
- **कृषि मंत्रालय द्वारा 20 जिलों में प्रायोगिक आधार पर एक कृषि आय बीमा योजना शुरू की गई है। इसका आगामी खरीफ मौसम से देश के 100 जिलों में विस्तार किया जाएगा। इसका ब्यौरा कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाएगा।**
- **स्वयं-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को उल्लेखनीय रूप से सफलता मिली है लेकिन देश के केवल कुछ राज्यों में ही ऐसा हुआ है। अतः नाबार्ड से उन राज्यों में जहां इस कार्यक्रम को अभी गति पकड़नी है, एक विशेष संवर्धनात्मक अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके पहले चरण में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में एक गहन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के बैंक भी दूसरे राज्यों में इस प्रयास में सहयोग करेंगे।**
- **चाय एक महत्वपूर्ण कृषि-प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें उत्तरी बंगाल, असम, पूर्वोत्तर और कुछ दक्षिणी राज्यों के हमारे लोग बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। इस समय यह उद्योग बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ है। इसीलिए मैंने भारतीय बैंक संघ को एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने का काम सौंपा है। इसे अब अंतिम रूप दिया गया है। इसके लिए एक विशेष चाय सावधि ऋण दिया जाएगा जिसे एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित पांच वर्ष में वापस अदा किया जा सकेगा। छोटे चाय उत्पादकों के मामले में बैंक 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर नए शिरे से कार्यशील पूंजी की सीमा 2 लाख रुपए तक करने को राजी हो गए हैं।**
- **इसके अतिरिक्त, चाय वागान क्षेत्र में एक ऋण सुधार योजना की व्यवहार्यता की जांच करने के कदम भी उठाए जाएंगे।**
- **देश का एक अन्य प्रमुख कृषि-प्रसंस्करण उद्योग, चीनी है जो बड़ी संख्या में रोजगार जुटाता है, परंतु इस समय यह अनेक जटिल समस्याओं के जाल में फंसा हुआ है। अतः सरकार सभी श्रेयधारकों के परामर्श से इस उद्योग के पुनरोत्थान के लिए एक पैकेज तैयार करेगी। इस बीच, एक अस्थाई राहत के उपाय के रूप में बैंकों सहित ऋणदाता एजेंसियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के परामर्श से चीनी कारखानों द्वारा लिए गए ऋणों को पुनर्संरचित करने की जांच की जाएगी।**

11. सहकारी बैंकों ने ग्रामीण ऋण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनकी भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिनसे वाजिब ब्याज की दरों पर कर्ज देने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। सहकारी ऋण ढांचे में नई जान डालने के लिए एक योजना तैयार की गई है जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रूपए का परिव्यय परिकल्पित है और जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच एक उचित अनुपात में हिस्सेदारी होगी। इस योजना को एक संशोधित विनियामक ढांचे के अमल में आते ही शुरु करने का प्रस्ताव है।

पशुधन विकास

12. पशु हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अति महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं। इस आर्थिक धंधे के समूचे दायरे, जैसे पशुपालन, दुग्ध उद्योग, भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार उपयुक्त बजटीय सहायता से एक राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना पर विचार करेगी।

लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड

13. लघु और स्वरोजगारयुक्त उद्यमों के विकास को और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम को उदार बनाने के उपाय किए गए हैं जिससे छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए बैंक ऋण लेना आसान हुआ है। अब, भारतीय बैंक संघ के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी बैंक उन उधारकर्ताओं के लिए, जिनका पिछला रिकार्ड संतोषजनक रहा हो, उनके कार्डों की ऋण-सीमा 2 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपए करेंगे। बैंकों को यह संशोधित योजना 1 मार्च, 2004 से लागू करने की सलाह दी जा रही है।

स्टाम्प शुल्क सुधार

14. राज्य सरकारों के परामर्श से समूची शुल्क व्यवस्था के व्यापक सुधार की योजना तैयार की जा रही है क्योंकि अधिक स्टाम्प शुल्क से लेन-देन की लागतें बढ़ती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में रुकावटें आती हैं। इस बीच सरकार ने ऐसी सभी लिखतों पर स्टाम्प शुल्क घटाने का निर्णय किया है, जहां दरें निर्धारित करने का प्राधिकार केन्द्र सरकार का है। पहले कदम के रूप में और पहली कटौती के तौर पर केन्द्रीय सरकार के सभी स्टाम्प पेपरों पर मौजूदा स्टाम्प शुल्क ढांचे को आधा किया जा रहा है अर्थात् इसमें 50 प्रतिशत की कमी की जा रही है। जहां तक प्राप्ति पर शुल्क का प्रश्न है, यहां भी स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आरंभिक सीमा 500 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए की जानी है। परन्तु इस अंतिम सुधार के लिए इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, अतः इसे इस अवस्था में शुरु नहीं किया जा सकता है।

विशेष क्षेत्र

द्वीप क्षेत्र

15. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में निकोबार जिला हमारे सबसे दूर के जिलों में से एक है। ये द्वीप समुद्र से पार काफी दूरियों पर अलग-अलग स्थित हैं और अपेक्षाकृत दुर्गम हैं। अतः निकोबार द्वीपसमूह में, यहां तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2004 से मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर पर दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा।

16. निर्माण की उच्च लागत के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्रचलित अधिक मकान किरायों के कारण और प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि पोर्ट ब्लेयर का दर्जा मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 'सी' से बढ़ाकर 'बी-1' श्रेणी का कर दिया जाए। इसके साथ ही अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों और सम्पूर्ण लक्षद्वीप

संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा भी इस भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु उनके मौजूदा 'अवर्गीकृत' से बढ़ाकर 'सी' वर्ग का कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप संघ राज्य क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के अन्य सभी क्षेत्रों और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में भी मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। गोवा राज्य का दर्जा भी, मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 1 अप्रैल, 2004 से 'सी' से बढ़ाकर 'बी-1' किया जा रहा है।

मरुस्थली क्षेत्र

17. देश के मरुस्थली क्षेत्र कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश या तो सीमावर्ती जिले हैं अथवा उनसे सटे हुए हैं। पिछले वर्ष मैंने राजस्थान के मरुस्थली जिलों में पारंपरिक चारागाहों के पुनर्स्थापन और विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम 'मरु गोचर यांजना' घोषित की थी। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए खुशी है कि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन आरंभ हो चुका है। मैं अब हमारे मरुस्थलों में आजीविका के स्थायी साधनों की समस्या को दूर करने के शासनादेश के साथ मरुस्थली क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। यह टास्क फोर्स सभी प्रासंगिक वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा, कमियों की पहचान करेगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करेगा और उपयुक्त सिफारिश करेगा। यह किसी एक मरुस्थली जिले में एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की जांच करेगा और इस बारे में अपनी सिफारिशें देगा।

18. इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर दशकों से मन्थर गति से काम चल रहा है और यह वर्ष-दर-वर्ष मरुस्थल से होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। इसके पूरा होने में असाधारण देरी और हमारे मरुस्थली इलाकों में पानी के सर्वाधिक महत्व पर विचार करते हुए, इस नहर परियोजना के काम में इसके बाद एक नई केन्द्र-राज्य पहल के जरिए तेजी लाई जाएगी जिसमें निधिपोषण की अतिरिक्त और नई व्यवस्था होगी। इसी तरह नर्मदा नहर के राजस्थान में विस्तार हेतु भी वित्त मंत्रालय राजस्थान सरकार के साथ एक योजना तैयार करेगा और इसे जल्दी पूरा करने के लिए इसके वित्तपोषण में सहायता करेगा।

कच्छ और इसके निकटवर्ती जिले

19. इस समय गुजरात के कच्छ जिलों में 31 जुलाई, 2001 से 31 जुलाई, 2004 तक की अवधि के दौरान स्थापित नई औद्योगिक इकाइयां जो 31 जुलाई, 2004 को या इससे पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती हैं, उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ अधिक समय देने के उद्देश्य से, मैं इन नई इकाइयों की स्थापना के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2004 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2004 कर रहा हूं। उत्पाद शुल्क से छूट की अवधि वाणिज्यिक उत्पाद शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष बनी रहेगी।

महानगरों में जल की कमी

20. इस सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल की सुनिश्चित आपूर्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान देने के लिए कई पहलों की गई हैं। महानगरों को अब तक इस कमी को या तो स्वयं के नगरीय संसाधनों से या उनकी संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सहायता के बल पर दूर किया जाता था। अतिरिक्त आपूर्ति उपायों की तुलना में, जल की आवश्यकता और मांग अधिक तेजी से बढ़ी है। इसलिए प्रधान मंत्री ने बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली तथा हैदराबाद जैसे महानगरों के लिए एक त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। महानगरों में अवसंरचना विकास हेतु मौजूदा केन्द्रीय योजना के लिए प्रावधान को अवसंरचना निधि, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा ऐसे ही अन्य निधिकरण स्रोतों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा

संबंधित व्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह योजना 1 मार्च, 2004 तक प्रचालन में आ जाए।

कन्वेंसन सेंटर

21. सरकार ने अब विश्व स्तर के चार अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जिनकी स्थापना निजी-सरकारी सहभागिता से की जाएगी, के लिए स्थानों का चयन कर लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि इन में से दो केन्द्र दिल्ली और मुंबई के महानगरों में तथा एक-एक केन्द्र गोवा और राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। गोवा तथा राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं लेकिन इनके लिए और अधिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता है। इससे, गोवा भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों के आयोजन हेतु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। जयपुर में कन्वेंसन सेंटर प्रभावी रूप से कार्य कर सके, इसके लिए जयपुर के हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इनके बारे में शीघ्र ही व्यौरों की घोषणा की जाएगी।

विकास वित्त

22. विकास वित्त का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के पुनरुद्धार तथा पुनर्संरचना संबंधी उपायों पर पहले से ही कार्य चल रहा है। संसद के आदेश के अनुसार, वित्त मंत्रालय एक विकास वित्त संस्थान के रूप में आई.डी.बी.आई. की भूमिका के परिरक्षण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

23. मौजूदा आर्थिक विकास प्रणाली के लिए सतत तथा संवर्धित निवेश की आवश्यकता है। इसके लिए उपयुक्त दरों पर तथा एक समन्वित तरीके से समय पर धनराशि उपलब्ध करवानी होगी। चूंकि, पुनर्गठित आई.डी.बी.आई. के पास अपेक्षित विशेषज्ञता है और उसे परियोजना मूल्यांकन, निधिकरण तथा समन्वय का अनुभव भी है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आई.डी.बी.आई. को प्रमुख विकासात्मक वित्त संस्था के रूप में नामित किया जाए। इस कार्य के लिए सरकार आई.डी.बी.आई. को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। आई.डी.बी.आई. के प्रयासों को पूरा करने में अन्य प्रमुख संस्थाओं तथा बैंकों जैसे अवसंरचना विकास वित्त निगम तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

24. इसी प्रकार, अनर्जक परिसंपत्तियों को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी में अंतरित करके तथा एक बड़े सरकारी बैंक में विलय करके भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) को पुनर्गठित किया जाएगा। अपने रूपांतरण के पश्चात्, ये दोनों संस्थान आई.डी.बी.आई. तथा आई.एफ.सी.आई. नए वित्तीय वर्ष में कार्य करने लगेंगे।

अन्य योजनाएं

25. कृषि अवसंरचना तथा ऋण निधि, लघु और मध्यम उद्यम निधि तथा औद्योगिक अवसंरचना निधि शीघ्र ही कार्यशील हो जाएंगी। ये तीनों निधियां, वित्तीय विवेक संबंधी मानदंडों से समझौता किए बिना, अधिक प्रतियोगी दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगी जिसके न्यूनतम उधार दर (पी.एल.आर.) से 2 प्रतिशतांक कम होने का अनुमान है।

26. मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि कृषि अवसंरचना तथा ऋण निधि द्वारा बंजरभूमि विकास, मौजूदा लेकिन अछूरी लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई के नए निर्माण कार्यों को पूरा करने, कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण, प्रमाणन तथा भंडारण तथा आधुनिक बूचड़खानों के निर्माण जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु ऋण-सहायता प्रदान की जाएगी। इस

निधि को 'लोक नायक जय प्रकाश नारायण निधि' नाम दिया जाएगा। इसी प्रकार, लघु तथा मध्यम उद्यम निधि द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उच्च प्रतियोगी दरों पर वित्तीय संसाधनों की कमी तथा कुछ मझोले उद्यमों के लिये सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) की सेवाओं का विस्तार न होने जैसी समस्या का निवारण किया जाएगा। औद्योगिक अवसंरचना निधि विद्युत उत्पादन, समुद्रपत्तनों, विमानपत्तनों, सड़कों, पर्यटन, दूरसंचार तथा नगर पालिका सेवाओं, जल आपूर्ति, मल-जल निकास तथा पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं जैसी शहरी अवसंरचना हेतु उच्च प्रतियोगी दरों पर ऋण प्रदान करेगी।

रक्षा आधुनिकीकरण निधि

27. रक्षा संबंधी खरीद प्रक्रिया में प्रायः तीन वर्ष से अधिक समय लग जाता है। इतनी अवधि के दौरान, रक्षा आधुनिकीकरण तथा हथियार प्रणाली खरीद के लिए पर्याप्त तथा वचनबद्ध निधियों की उपलब्धता के संतोषजनक समाधान की आवश्यकता होती है। तदनुसार 25,000 करोड़ रुपये की राशि वाली एक अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इससे, उक्त प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। रक्षा मंत्रालय को यह निधि नए द्वितीय वर्ष से प्रदान की जाएगी।

कर्मचारी कल्याण

28. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब मंहगाई भत्ता, वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो उसका मूल वेतन के साथ विलयन कर दिया जाना चाहिए। इस समय, मंहगाई भत्ता वेतन का 59 प्रतिशत है। सरकार ने इस सिफारिश पर गहन पुनर्विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि वेतन के 50 प्रतिशत तक के मंहगाई भत्ते का मूल वेतन के साथ विलयन कर दिया जाएगा। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा।

प्रत्यक्ष कर

29. आय कर प्रक्रिया में कुछ अनिवार्य परिवर्तनों के कारण आय कर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि, अधिनियम में अभी किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है लेकिन सरकार की यह धारणा है तथा हमारी वचनबद्धता है कि

- विद्युत क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध राजकोषीय लाभ 2006 तक की अवधि की बजाए 2012 तक के लिए बढ़ा दिए जाएं तथा ये लाभ राज्य बिजली बोर्डों से अधिकार में लिए गए (टेक-ओवर) मामलों में भी उपलब्ध कराये जाएं।
- 1 मार्च, 2003 को अथवा इसके पश्चात अधिग्रहीत सूखेबंद इक्विटियों को प्रदत्त दीर्घाधिक पंजीगत अनुलाभ कर से छूट की व्यवस्था को और तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए जिससे स्थायित्व प्रदान किया जा सके।
- विश्व नौवहन टनभार के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर करधान की बहुत निम्न दरें लागू होती हैं। एक ऐसा समान स्तर प्रदान करने के लिए जिससे भारतीय नौवहन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मुकाबला कर सके, निवल पंजीकृत टनभार के आधार पर, एक निश्चित दर पर कल्पित आय के साथ एक टनभार कर योजना पर विचार किया जाना चाहिए।
- जब सरकार द्वारा किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो पंजीगत अनुलाभ तथा बढ़ाये गये मुआवजे पर संचित ब्याज पर कर लगाए जाने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार का मानना है कि ऐसे

अधिग्रहण से मिलने वाले पूंजीगत अनुलाभ को कर से मुक्त रखा जाना चाहिए।
ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्धित मुआवजे पर अर्जित ब्याज के संबंध में भी
स्रोत पर कर की कटौती नहीं होनी चाहिए।

30. कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) के अंतर्गत रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि ये विदेशी-स्रोत सेवाएं, अनुषंगी और सहायक किस्म की हैं तथा भारतीय काल सेंटर्स को समुचित पारिश्रमिक की अदायगी की जाती है तो भारत में कार्यरत विदेशी-स्रोत वाली कंपनी पर कर नहीं लगाया जाएगा। यह नीति आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के मानदंडों तथा दोहरे कराधान से बचने के समझौतों के अनुरूप है।

31. सरकार का यह भी दृढ़ विश्वास है कि वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु जिनका कर अनुपालन में निःसन्देह सर्वोत्कृष्ट रिकार्ड रहा है, आय कर प्रयोजन हेतु मानक कटौती के संशोधन के मुद्दे पर अब नए सिरे से विचार किया जाए। इसके अलावा, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की परिवार पेंशन पर कर की समीक्षा करना भी जरूरी है ताकि वे एक प्रतिष्ठा का जीवन व्यतीत कर सकें। हमें मौजूदा छूट सीमाओं की समीक्षा करने और उन्हें नए सिरे से उपयुक्त तरीके से पुनः निर्धारित करने की भी आवश्यकता है।

अप्रत्यक्ष कर

32. विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु, सरकार ने पहले ही 8 जनवरी, 2004 को कुछ उपायों की घोषणा की है। ये उपाय सामयिक तथा आवश्यक थे, मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा।

पूंजीगत सामान

33. हमारे घरेलू उद्योग को आयातित पूंजीगत सामानों से प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु जिन पर अभी 10 प्रतिशत का प्राथमिक सीमाशुल्क लगाया जाता है, मैंने ऐसे शुल्क को अनेक कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा उनके विनिर्माण हेतु संघटकों पर पहले ही घटा दिया है। इसकी वजह से विसंगति दूर हुई है।

34. एक सुझाव यह भी आया है कि जहां कहीं आयातित पूंजीगत सामान पर प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है, वहां स्वदेश में निर्मित ऐसे ही पूंजीगत सामान को भी सम निर्यात लाभ प्रदान किये जाने चाहिए। जहां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से अधिप्राप्ति की जाती है, ऐसी विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्यात लाभ प्रदान करने की एक स्कीम पहले से अस्तित्व में है। फिर भी वित्त मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श कर इस सुझाव की जांच करेगा ताकि घरेलू विनिर्माताओं के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जा सके।

विद्युत

35. विद्युत क्षेत्र निवेश तथा सुधारों से सम्बन्धित कार्यबल ने विद्युत क्षेत्र हेतु प्रतिकारी शुल्क को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर योग्य बनाने की सम्भावना का पता लगाने की सिफारिश की है। इस सुझाव की भी जांच की जाएगी।

36. पिछले बजट में, विद्युत उत्पादन हेतु अवशिष्ट ईंधन तेल पर उत्पाद शुल्क से छूट, जो विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों को ही उपलब्ध थी, का विस्तार विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त उत्पादन कम्पनियों के लिये भी किया गया था। यह अनुरोध किया गया है कि 1948 के अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त इकाइयों पर इस छूट को अब पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए यदि कभी विद्युत की आपूर्ति

राज्य विद्युत बोर्डों को की गई थी और इसकी उत्पादन लागत विद्युत खरीद करारों द्वारा शासित की गई थी। मेरा यह मानना है कि इस प्रकार की पूर्वव्यापी छूट हेतु एक उपयुक्त विधायी उपाय पर विचार किया जाना चाहिए।

सामान नियमावली

37. हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के आगमन हॉलों में स्थित सीमाशुल्क काउंटरों पर भीड़भाड़ को और कम करने हेतु निःशुल्क सामान छूट को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा रहा है। ऐसे सामान पर सीमाशुल्क भी 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। यह आज से प्रभावी होगा।

प्रयोक्ता अनुकूल कर प्रशासन

38. सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग और अपेक्षाकृत कम अनुपालन लागतों वाली, मनमानी-रहित, निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से उन्नत कर प्रशासन की ओर बढ़ना जारी रहना चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुझे निम्नलिखित घोषणाएं करते हुए प्रसन्नता हो रही है:-

- सामानों की निकासी हेतु सीमाशुल्क दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, जो इस समय चौबीसों घंटे 9 सीमाशुल्क केन्द्रों में उपलब्ध है, को 31 मार्च, 2004 तक 23 केन्द्रों में लागू कर दिया जाएगा;
- 30 जून, 2004 से सीमाशुल्क निकासी स्वमूल्यांकन तथा चुनिंदा परीक्षण पर आधारित होगी;
- बेहतर पारदर्शिता लाने, वर्गीकरण सम्बन्धी विवाद से बचने तथा सीमाशुल्क और निर्यात-आयात नीति वर्गीकरण के साथ सीमाशुल्क के वर्गीकरण का सामंजस्य बैठाने हेतु 30 सितम्बर, 2004 तक सीमाशुल्क लगाने के लिए एक 8-अंकीय सामान कूट वर्गीकरण को अपनाया जाएगा;
- विवादों के शीघ्र निपटान हेतु संघ उत्पाद नियमावली के अन्तर्गत अपराधों का प्रशमन 30 जून, 2004 से प्रारम्भ किया जाएगा; और
- उत्पाद शुल्क की स्वचालित प्रक्रिया को बढ़ाने तथा राजस्व खातों के बेहतर मिलान हेतु 30 जून, 2004 से उत्पाद शुल्क विवरणियों की ईन्फाइलिंग प्रणाली प्रारम्भ की जाएगी।

सेवा कर

39. राजस्व के एक विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सेवाओं पर कर लगाने हेतु संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पहले ही चल रही है। अन्तरिम तौर पर, सेवा कर पिछले बजट में सात नई सेवाओं पर लगाया गया था। विवरणियां भरने को सरल बनाने तथा राजस्व के इस महत्वपूर्ण स्रोत के अन्तर्गत अनुपालन लागत को घटाने के लिए, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2 जनवरी, 2004 से -

- सेवा कर के लिए पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने हेतु केवल एक सामान्य सत्यापन की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
- एक से अधिक कराधेय सेवा देने वाले मूल्यांकितियों के लिए एकल पंजीकरण और एकल विवरणी है; और

- विवरणियों की ई-फाइलिंग और इनकी इलैक्ट्रॉनिक जांच का विस्तार भी 10 सेवाओं से सभी 58 कर योग्य सेवाओं तक करते हुए सेवा कर स्वचालन को बढ़ाया गया है।

IV. संशोधित और बजट अनुमान

40. मैं अब सदन को चालू वर्ष के साथ-साथ 2004-05 के हमारे हिसाब किताब की मुख्य बातों के बारे में सूचित करना चाहूंगा।

वर्ष 2003-2004 के संशोधित अनुमान

41. बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान, व्यय में 11,143 करोड़ रुपए की निवल कमी दर्शाते हैं। व्यय में यह कमी ग्रामीण विकास, सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना और रेलवे के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता संबंधी अतिरिक्त व्यय के बावजूद प्राप्त की गई है।

42. केन्द्र के निवल कर राजस्व 184,169 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 3,370 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 187,539 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। कर-भिन्न राजस्व 69,766 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर से 5,722 करोड़ रुपए अधिक होकर 75,488 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विनिवेश प्राप्तियां भी 13,200 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में अधिक अर्थात् 14,500 करोड़ रुपए हैं।

43. केंद्र की संशोधित राजस्व प्राप्तियां 263,027 करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा 132,103 करोड़ रुपए जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत है तथा राजस्व घाटा 99,860 करोड़ रुपए है जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

44. महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मानेंगे और इस तथ्य का अनुमोदन करेंगे कि सरकार ने बजटीय लक्ष्यों की तुलना में बेहतर कार्य निष्पादन करके राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के बारे में अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान

45. वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान में कुल व्यय 457,434 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें 135,071 करोड़ रुपए आयोजना और 322,363 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न के लिए हैं।

आयोजना व्यय

46. एक ओर विकासात्मक आवश्यकताओं और दूसरी ओर राजकोषीय स्थायित्व के बीच सही संतुलन बनाए रखने के लिए वर्ष 2004-05 की आयोजना के लिए सकल बजटीय समर्थन 135,071 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 14,097 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें से 81,367 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 9,215 करोड़ रुपए या 12.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इसी तरह, राज्य आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता 53,704 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष से 4,882 करोड़ रुपए अधिक है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी नई स्कीमों के लिए आवश्यकता हुई तो सरकार ऐसी स्कीमों के लिए अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था करेगी।

आयोजना भिन्न व्यय

47. वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान आयोजना-भिन्न व्यय में 16,218 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि दर्शाते हैं। यह वृद्धि मुख्यतया व्याज भुगतान और ऋण शोधन (4,945 करोड़ रुपए), रक्षा (5,700 करोड़ रुपए), राज्य सरकारों को अनुदान एवं ऋण (4,110 करोड़ रुपए) और खाद्य सब्सिडी (2,600 करोड़ रुपए) में है।

राजस्व अनुमान और राजकोषीय घाटा

48. अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों के साथ मैं केन्द्र की 290,882 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों और 136,452 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाता हूँ जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत है तथा 89,860 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान करता हूँ जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत है।

V. निष्कर्ष

49. महोदय, मुझे जुलाई, 2002 में वित्त मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मैंने यहां पर मात्र लगभग डेढ़ वर्ष कार्य किया है। इस अवधि के दौरान यह देखना मेरा विशेष कार्य रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 7.5 से 8 प्रतिशत के आसपास स्थिर और सशक्त रूप से वृद्धि के मार्ग पर बढ़ती रहे। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अपनाए गए सुधारों, इस मंत्रालय में मेरे पूर्ववर्ती माननीय श्री यशवंत सिन्हा के योगदान और सर्वाधिक रूप से प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा दिये गये समर्थन व नेतृत्व के कारण संभव हुआ है।

50. श्री वाजपेयी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 19 मार्च, 1998 से पोखरन के बाद के आर्थिक प्रतिबंधों, पूर्व एशियाई संकट, कम से कम दो बड़े विनाशकारी तूफानों, अभूतपूर्व सूखे, भुज में विध्वंसकारी भूकंप, सीमा पर दो संघर्षों, आतंकवाद और विद्रोह की चुनौती, खाड़ी युद्ध, वैश्विक मंदी, तेल के मूल्यों की अस्थिरता तथा अनेक समस्याओं का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इन अनेक चुनौतियों के बावजूद, इस अवधि के दौरान सरकार राजकोषीय घाटा कम करके इसे सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत, राजस्व घाटे को 3.6 प्रतिशत पर ले आई तथा मुद्रा स्फीति के वार्षिक औसत को 4.8 प्रतिशत के आसपास नियंत्रित रखा। वर्ष 1998-2004 की अवधि के दौरान हमारा राजस्व संग्रहण लगभग 83 प्रतिशत बढ़ा, हमारे पूंजी बाजार सुदृढ़ हैं, फूटीआई बाजार में फिर अग्रणी है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 100 बिलियन डालर से अधिक के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचकर लगभग चार गुना हो गये हैं, इस अवधि में हमारा सकल घरेलू उत्पाद लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय संतोष, राष्ट्रीय विश्वास और बेहतर वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने के हमारे सामूहिक संकल्प की जड़ें अब मजबूत हो गई हैं।

51. महोदय, मैं यह अंतरिम बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

एम. प्रसाद, संयुक्त सचिव (एफ आर बी एम)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2004

No. F. 2(53)-B(D)/2003.—The following is published for general information :—

Interim Budget 2004-2005

Speech of

Jaswant Singh

Minister of Finance

February 3, 2004

I. INTRODUCTION

Mr. Speaker,

1. I rise to present an Interim Budget, for part of the fiscal year 2004-05. This seeks a Vote-on-Account to enable the Government to discharge its responsibilities and to meet all essential expenditure during the first four months of 2004-05. The Demands for Grants and the Annual Financial Statement presented are, however, for the full financial year, though, these could be revised, as is normal, at the time of presentation of the regular Budget. I am also introducing a Finance Bill, seeking to continue the existing tax structure for the present.

2. Under the premiership of Shri Atal Bihari Vajpayee, this is the seventh successive budget of the Government of the National Democratic Alliance (NDA). On this occasion I share with the country and the House a sense of great satisfaction at the robust showing of our national economy, and also express our sincere gratitude for the cooperation, support and encouragement that the people of India have so consistently and so ungrudgingly given to the NDA and to its Government. The country's macro-economic situation is better than it has ever been in the last fifty years. Internationally, too, there is now much greater, and a much more widespread recognition that India is progressing in all spheres of national endeavour, that it has evolved into a stable economy, with assured growth, and enhanced national prosperity.

II. NDA: ECONOMIC POLICY – APPROACH AND ACHIEVEMENTS

3. This Government has consistently placed the citizens' well being at the core of its responsibilities. Our adherence to 'Four priorities' remains. The objectives of the life-time concerns of our citizens: enhanced employment, and eradication of poverty; a second green revolution in agriculture; infrastructure development; fiscal consolidation; and greater manufacturing sector efficiency, are our solemn commitments.

4. We believe, Sir, that both are necessary: a vision for a resurgent India and, simultaneously an awakening so that the disadvantaged of our land are lifted beyond poverty. We hold that economic development is not about economics alone, it is always, simultaneously, a political statement too, for 'development' devoid of compassion is a misnomer. Of course, growth statistics are very important; they are vital inputs, but they must also be the indices that assist us in designing distributive justice. It is for this reason that 'gross national contentment' is so important, as the catalyst that motivates redoubled national endeavour. It is from seeking national contentment that objectives are born: "*Gerib ke pet me dana, Grihini ki tukia mein anna.*" Sir, India must be amongst the leading economies of the world, that simply put is our national destiny; to be in service of the country's destiny is the Government's honour and its bounden duty. From this directly flow our national economic objectives.

5. Economic growth indices, in the current year, Mr. Speaker, are very encouraging. With inflation at 4 to 4.5 per cent, this year we expect the growth rate of our GDP to be between 7.5 and 8 per cent. Though, there are higher growth estimates that have been made, for the present, we prefer to remain with the cited figures. This level of growth is a matter of great satisfaction. Sir, employment has increased, but so have expectations. We must meet this challenge. Bold initiatives in infrastructure have already generated several layers of immediate employment, simultaneously laying the foundation for additional quality employment across a broad spectrum of economic activity. The objective of enhancing job opportunities will be pursued vigorously. Our foreign exchange reserves crossed US\$100 billion on December 19, 2003. They continue to grow, liberating us from the mentality of want. For greater openness and to share necessary information with citizens, the first ever Report of the Reserve Bank of India (RBI), on Foreign Exchange Reserves is being released today. It can be accessed on the Ministry's, as well as the RBI's website.

6. Sir, a combination of moderate inflation, declining interest rates, and healthy capital markets has set our economy on the path of accelerated growth. To further encourage this is our responsibility. Preserving the strength of our macroeconomic fundamentals has, therefore, to be much more focused. Management of the economy is a continuing responsibility, governance can neither pause nor cease, and measures to fully consolidate, and continuously enhance the growth momentum must always be adopted in time. Only in that manner can we realise the vision of economic and social progress that we have cherished since independence.

III. INITIATIVES AND THE ROAD AHEAD

Reform Measures

Antyodaya Anna Yojana

7. Antyodaya Anna Yojana, launched by the Prime Minister in December 2000, currently covers 1.5 crore families below the poverty line (BPL). This is a

highly successful programme, widely acclaimed. It directly addresses poverty alleviation and nutritional adequacy. This programme is now being extended by increasing its coverage to 2 crore BPL families. Whilst doing so, it will be ensured that tribal states, districts, or belts receive added allocations. This will be effective from April 1, 2004.

Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana

8. Poverty and disease are interlinked. Specialty hospitals in the private sector remain beyond the reach of many of our citizens. The Prime Minister had, therefore, last Independence Day, announced the establishing of six hospitals, in the Government sector, on the pattern of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). This 'Pradhanmantri Swasthya Suraksha Yojana' envisages six new AIIMS like hospitals, one each in the States of Bihar, Chhatisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, and Uttaranchal. Hon'ble Members are doubtless aware that no additional hospital on the pattern of AIIMS has been set up by any Government, since 1956. I would also like to mention that under this Pradhanmantri Swasthya Suraksha Yojana, one medical college each in the six States of Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, and West Bengal will also be upgraded to the level of AIIMS.

9. I am happy to announce that a provision for both these schemes has been made in this Budget itself.

Rural

10. The Government is committed to ensuring the availability of timely credit at affordable rates to our farmers, and to other citizens in rural India. For this objective, the following additional measures will be taken:

- In July, 2003, a reduction in the rate of interest for crop loans by public sector banks to 9 per cent was announced. The NABARD Act was also appropriately amended. I have been urging the Indian Banks' Association to further lower the interest rates for agricultural purposes. Some public sector banks have already done so. I am confident that other banks will also respond by offering loans at rates lower than those prevailing currently.
- Traditionally, banks have sought relatively higher security on credit for agriculture. To illustrate, banks insist on mortgaging the entire land holding of a farmer borrower, as security for advances for agricultural purposes. Banks are, therefore, now being advised to assess individual credit-worthiness and to not routinely insist on additional collateral through a mortgage of the entire land holding. As a principle, collateral security should be proportionate to the value of the loan.
- Prescriptions relating to Non-Performing Assets (NPAs), in relation to crop loan accounts, have posed problems in the provisioning of

credit to farmers where seasonality and uncertainty of farm incomes are not fully captured. A Committee has been set up under Dr.V.S. Vyas, an eminent agriculture economist, to address this issue. Suitable remedial measures will be recommended within 90 days.

- I expect all eligible farmers to be in receipt of their **Kisan Credit Cards** (KCC) by March 31, 2004. To extend the benefit of technological developments in the banking industry to rural India, the existing Kisan Credit Card will hereafter be modified, upon individual request, for use on ATM machines, wherever such facility exists.
 - A **Farm Income Insurance Scheme** has been introduced by the Ministry of Agriculture in 20 districts, on a pilot basis. This will be extended to 100 districts, of the country from the forthcoming Kharif season. Details will be announced by the Ministry of Agriculture.
 - **Self Help Groups** (SHGs) have been a remarkable success story, but only in some states of the country. NABARD has, therefore, been asked to take up a special promotional campaign in the States where this programme is yet to gather momentum. In the first phase, an intensive programme will, therefore, be launched in the states of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh. Public Sector Banks will also supplement this effort in other States.
 - **Tea** is an important agro-processing industry, employing a large number of our citizens in North Bengal, Assam, the North-East and some of the Southern States. Currently, this industry is beset by many problems. I had, therefore, tasked the Indian Banks Association to prepare a revival package. This has now been finalized. Special Tea Term Loan, repayable in five years, with a moratorium of one year, shall be provided. In case of small tea growers banks have agreed to extend fresh working capital limits up to Rs.2 lakh, at an interest rate of 9 per cent.
 - In addition, steps will be undertaken to examine the feasibility of a debt amelioration scheme in the **tea** sector, too.
 - **Sugar**, another major agro-processing industry of the country, generating substantial employment, currently faces a complex web of problems. Government will, therefore, prepare a package for the revitalisation of this industry, in consultation with all the stakeholders. In the meantime, as a measure of temporary relief, restructuring of loans taken by sugar factories will be examined by the lending agencies, including banks, in consultation with RBI and NABARD.
11. **Cooperative banks** have played a vital role in the delivery of rural credit. They, too, have a variety of problems hampering their capacity to deliver credit at reasonable rates of interest. A scheme to revitalize the cooperative

credit structure, envisaging an outlay of about Rs.15,000 crore, to be shared between the Central and State Governments, in an appropriate ratio, has been prepared. It is proposed to initiate this scheme as soon as the revised regulatory framework has been put in place.

Cattle Development

12. Cattle are a vital integral of our rural economy. To give a boost to the entire gamut of this economic activity, such as animal husbandry, dairying and sheep rearing, the Government will consider the setting up of a National Cattle Development Board with appropriate budgetary support.

Laghu Udyami Credit Cards

13. To further encourage the development of small-scale and self-employed ventures steps have been taken to liberalise Laghu Udyami Credit Card scheme, providing small and medium enterprises easier access to bank credit. It has now been decided, in consultation with IBA, that the public sector banks will increase the credit limit of their cards, for borrowers who have a satisfactory track record, from Rs.2 lakh to Rs.10 lakh. Banks are being advised to make the modified scheme operational from March 1, 2004.

Stamp Duty Reform

14. A comprehensive reform of the entire stamp duty regime is being addressed in consultation with State Governments, as high stamp duty increases transaction costs, restricting economic activity. The Government has, in the meantime, decided to reduce stamp duty on all such instruments where the authority to fix rates is of the Central Government. As a first step, and as the first reduction, the existing stamp duty structure is being halved, that is, being reduced by 50 per cent on all Central Government stamp papers. As for duty on Receipts, here too, the threshold for payment of stamp duty is to be increased from Rs.500 to Rs.50,000. As, however, this last reform requires an amendment to the Act, it can not be taken up at this stage.

Special Areas

Island territories

15. The district of Nicobar, in the Andaman and Nicobar Islands, is one of our remotest districts. These islands, separated by vast distances across the sea are relatively inaccessible. Therefore, in the Nicobar group of islands, a hard area allowance at the rate of 25 per cent of basic pay will, with effect from April 1, 2004, be paid to all Government employees posted there.

16. Due to high cost of construction, consequently the high rentals prevailing in this region, and as directed by the Prime Minister it has been decided that the status of Port Blair be raised from a 'C' to a 'B-1' class city, for purposes of house rent allowance (HRA). Simultaneously, rural areas of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and the entire Union Territory of Lakshadweep

will also stand upgraded from their existing status of 'unclassified' to 'C' class city, for the purpose of payment of this allowance. Consequently, HRA will also be raised from 7.5 per cent to 15 per cent of the basic pay in all other areas of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, as well as in the Union Territory of Lakshadweep. The status of State of Goa is also being raised from 'C' to 'B-1', from April 1, 2004, for the purposes of HRA.

Desert areas

17. The desert areas of the country are under a variety of stresses. Most of them are also either border districts or are contiguous to it. Last year, I had announced the 'Maru Gochar Yojana', a special programme for rehabilitation and development of traditional pasture lands in the desert districts of Rajasthan. I am glad to inform Hon'ble Members that implementation of this programme has commenced. I now propose to establish a Task Force for Integrated Development of Desert Areas, with a mandate to address the problem of sustainable livelihood in our deserts. This Task Force will review all relevant current programmes, identify gaps, define thrust areas, and make appropriate recommendations. It will also examine the establishment of a Rural Technology Centre, in one of the desert districts, and give its recommendations in this regard.

18. The Indira Gandhi canal project has languished for decades, slowly inching its way, year after year, through the desert. Considering the inordinate delay in its completion and the critical importance of water in our desert areas, this canal project will, hereafter, be accelerated through a fresh Centre-State initiative, including additional, innovative funding. Similarly, for an extension into Rajasthan of the Narmada Canal too, the Ministry of Finance will work with the Government of Rajasthan and assist it in financing an early completion.

Kutch and adjoining districts

19. At present, new industrial units in the Kutch Districts of Gujarat, established during the period from July 31, 2001 to July 31, 2004 and which start commercial production on or before July 31, 2004 are exempt from excise duty. In order to give some more time for completion of such projects, I am extending the last date, for setting up of such new units, from July 31, 2004 to December 31, 2004. The period of exemption from excise duty will continue to be five years from the date of start of commercial production.

Water Scarcity in Metropolitan Cities

20. Several initiatives have been taken by this Government to address the vital question of providing an assured supply of potable water to rural India. Metropolitan cities have until now had to address this shortage through either their own municipal resources or on the strength of support received from their respective State Governments. The need and demand for water has grown much faster than additional supply measures. The Prime Minister has, therefore, decided to initiate an accelerated drinking water supply scheme for mega cities, such as Bangalore, Chennai, Delhi and Hyderabad. The provision for existing

Central scheme for infrastructure development in mega-cities will be augmented by accessing the Infrastructure Fund, the Life Insurance Corporation and other such funding sources. Details will be finalised by the Ministry of Finance to ensure that the scheme is operational by March 1, 2004.

Convention Centres

21. Government has now decided upon the venues for four global standard international convention centres, to be established through private-public partnership. I am glad that two of these will be located in the metropolitan cities of Delhi and Mumbai, and one each in Goa and Rajasthan. Both Goa and Rajasthan have great tourism potential, but need more infrastructural facilities. Goa will thus also be enabled to provide suitable facilities for holding international film festivals. So that the convention centre in Jaipur functions effectively, the airport in Jaipur will be converted into an international airport. Details of all these will be announced shortly.

Development Finance

22. There is no alternative to development finance. Steps to revive and re-structure the Industrial Development Bank of India (IDBI) are already in hand. In accordance with the mandate of the Parliament, the Ministry of Finance is committed to preserving and strengthening the IDBI's role as a development financial institution.

23. The current economic growth pattern requires continuous and added investment. For this, finance has to be made available timely, at reasonable rates and in a coordinated manner. Since the restructured IDBI has the requisite expertise, also experience in project appraisal, funding and coordination, it has been decided to designate IDBI as the lead developmental finance institution. Government will provide necessary support to IDBI for this task. IDBI's effort will be complemented by other premier institutions and banks such as the Infrastructure Development Finance Corporation and the State Bank of India.

24. Similarly, the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) will be restructured through transfer of its impaired assets to an Asset Reconstruction Company and merger with a large public sector bank. Both these institutions, the IDBI and IFCI, should be functional in the new financial year after their transformation.

Other Schemes

25. The Agricultural Infrastructure and Credit Fund, the Small and Medium Enterprise Fund, and the Industrial Infrastructure Fund will be operational shortly. All the three funds will, without compromising the norms of financial prudence, provide credit at highly competitive rates, which is expected to be 2 percentage points below the Prime Lending Rate (PLR).

26. I wish to reiterate that the Agricultural Infrastructure and Credit Fund will provide credit support to infrastructure facilities such as wasteland

development, completion of existing but incomplete minor irrigation projects plus new minor irrigation works, grading, certification, and storage of agro-products, and construction of modern abattoirs. This Fund will be called '**Lok Nayak Jai Prakash Narayan Fund**'. Similarly, the SME Fund will address the problem of inadequacy of financial resources, at highly competitive rates for the small-scale sector, and a lack of SIDBI coverage for some of the medium-sized enterprises. The Industrial Infrastructure Fund will provide credit at highly competitive rates for power generation, seaports, airports, roads, tourism, telecommunication, and urban infrastructure like municipal services, water supply, sewage disposal and environmental projects.

Defence Modernisation Fund

27. The process of defence procurement often extends to over three years. Adequate and a committed availability of funds, over such a period, for defence modernisation and weapons systems acquisition needs a satisfactory resolution. It has accordingly been decided to establish a non-lapsable, Defence Modernisation Fund of Rs.25,000 crore. This will commit availability of adequate funds for the purpose. The Fund will be made available to the Ministry of Defence from the new financial year.

Employee Welfare

28. The Fifth Central Pay Commission had recommended that Dearness Allowance (DA) should be merged with basic pay whenever the DA exceeds 50 per cent of pay. At present, DA is at 59 per cent of pay. The Government having re-examined this recommendation in detail has therefore, decided that DA, to the extent of 50 per cent of pay, will be merged with basic pay. This will take effect from April 1, 2004.

Direct taxes

29. Some necessary changes in Income Tax procedures require the amendment of the Income Tax Act. While changes in the Act are currently not being proposed, it is the conviction of the Government, also our commitment that

- Fiscal benefits available to new projects in the power sector should be extended up to 2012, instead of 2006, and also be available to cases of take-over from State Electricity Boards.
- The regime of listed equities acquired on or after March 1, 2003 being exempt from long-term capital gains tax should be extended for a further period of three years, so as to provide stability.
- More than 90 per cent of world shipping tonnage is subject to very low levels of taxation. To provide a level playing field so that Indian shipping becomes internationally competitive, a tonnage tax scheme, with notional income at a fixed rate, on the basis of net registered tonnage should be considered.

- Farmers face hardship on account of levy of tax on capital gains, and accrued interest on enhanced compensation, when their agricultural land is acquired by the Government. The Government believes that capital gains on such acquisition should be exempt from tax. There should also be no deduction of tax at source on the interest earned on enhanced compensation for acquisition of such land.

30. Business Process Outsourcing (BPO) has scope for employment generation. It has been clarified that if outsourced services are ancillary and auxiliary in nature and adequate remuneration is paid to the Indian call centre, then there shall be no tax on such foreign company as has outsourced its activity to India. This policy is on the lines of OECD norms and double taxation avoidance agreements.

31. It is also the conviction of the Government that for the salaried class, which doubtless has the best track record of tax compliance, the issue of revising the standard deduction for Income Tax purposes has now to be revisited. Furthermore, the tax treatment of family pension of war widows merits a review so as to enable them to live a life of dignity. We also need to revisit the present exemption limits and to realign them appropriately.

Indirect taxes

32. For consolidating the growth process, the Government has already announced some measures on January 8, 2004. These steps were timely and necessary. I shall not repeat them.

Capital goods

33. To enable our domestic industry to compete with imported capital goods, which are currently subject to a 10 per cent basic customs duty, I have already reduced such duty on a number of raw materials, intermediates and components for their manufacture. This has removed an anomaly.

34. A suggestion has been made that wherever there is exemption from countervailing duty on an imported capital good, deemed export benefits ought to be given to the very same capital good, indigenously manufactured. There already exists a scheme for giving deemed export benefits for specified projects, where procurement is through international competitive bidding. Ministry of Finance, in consultation with Ministry of Commerce, will nevertheless, examine this suggestion in order to provide a level playing field to domestic manufacturers.

Power

35. The Task Force on Power Sector Investment and Reforms has recommended exploring the possibility of making countervailing duty for the power sector leviable. This suggestion, too, will be examined.

36. In the last budget, exemption from excise duty on residual fuel oils for generation of power, available only to units licensed under the Electricity Act 1910, was extended to generating companies licensed under the Electricity Supply Act 1948. It has been requested that this exemption, for units licensed under the 1948 Act, may now be made applicable retrospectively, whenever electricity was supplied to State Electricity Boards, and the cost of generation was governed by power purchase agreements. I believe that a suitable legislative measure for a retrospective exemption of this nature should be considered.

Baggage rules

37. To further reduce congestion at the customs counters in the arrival halls of our international airports, free baggage allowance is being raised from Rs.12,000 to Rs.25,000. Customs duty on such baggage is also being reduced from 50 per cent to 40 per cent. This will be effective from today.

User-friendly tax administration

38. The move towards an improved tax administration through greater application of IT, and a discretion-free, impersonal system with lower compliance costs must continue. It is with this objective in mind, that I am pleased to announce

- round the clock electronic filing of customs documents for clearance of goods, presently available in 9 customs formations will be extended to 23 customs formations by March 31, 2004;
- customs clearance will be based on self-assessment and selective examination from June 30, 2004;
- an 8-digit code classification of goods for the levy of excise will be adopted by September 30, 2004, to bring greater transparency, avoid classification dispute, and harmonise excise classification with customs and EXIM Policy nomenclature;
- compounding of offences under Union excise rules, for quick settlement of disputes, will be introduced from June 30, 2004; and
- e-filing of excise returns will be introduced from June 30, 2004 to enhance excise automation and for better reconciliation of revenue accounts.

Service tax

39. To enable levy of tax on services as a specific and important source of revenue, an amendment to the Constitution is already in progress. In the interim, the service tax was extended to seven new services in the last Budget. To facilitate the filing of returns and to reduce the compliance cost under this important source of revenue, I am glad to announce that from January 2, 2004

- only a simple verification is being made for grant of registration for service tax;

- there is a single registration and single return for assesses providing more than one taxable service; and
- service tax automation has been enhanced by extending e-filing of returns and also their electronic scrutiny from 10 services to all the 58 taxable services.

IV. REVISED AND BUDGET ESTIMATES

40. I must now inform the House about the essentials of our book-keeping for the current year, as also for 2004-05.

Revised Estimates for 2003-2004

41. The Revised Estimates show a net decrease in expenditure of Rs.11,143 crore as compared to the Budget estimates. This reduction in expenditure has been achieved despite additional expenditure on Rural Development, the Sarva Shiksha Abhiyan, the Delhi Metro Rail Project and additional budgetary support for the Railways.

42. Net tax revenues for the Centre are estimated at Rs.187,539 crore compared to the Budget estimate of Rs.184,169 crore, an increase of Rs.3,370 crore. Non tax revenue is estimated at Rs.75,488 crore, Rs.5722 crore more than the estimated level of Rs.69,766 crore. Disinvestment receipts, at Rs.14,500 crore, are also higher than the budget estimate of Rs.13,200 crore.

43. The revised revenue receipts of the Centre are estimated at Rs.263,027 crore, the fiscal deficit at Rs.132,103 crore which is 4.8 per cent of the estimated GDP and the revenue deficit at Rs.99,860 crore which is 3.6 per cent of the estimated GDP.

44. I trust Sir, that Hon'ble Members would observe, and approve of the fact that the Government has demonstrated its resolve about fiscal consolidation by performing better than the budgeted targets.

Budget Estimates for 2004-2005

45. In the budget estimates for 2004-2005, the total expenditure is estimated at Rs.457,434 crore, of which Rs.135,071 crore is for Plan and Rs.322,363 crore for non-Plan.

Plan expenditure

46. In order to strike the right balance between the developmental needs on one hand and fiscal stability on the other, the Gross Budgetary Support (GBS) for Plan 2004-05 has been fixed at Rs.135,071 crore. This is Rs.14,097 crore more than last year, indicating an increase of 11.6 per cent. Out of this, an amount of Rs.81,367 crore is being provided as Budget support for Central Plan. This is an increase of Rs.9,215 crore, or 12.8 per cent, over the last year. Similarly, the Central Assistance for State Plans is Rs.53,704 crore, which is Rs.4,882 crore more than last year. Should need arise for new schemes, such

as Providing Urban Amenities in Rural Areas (PURA), the Government will then provide additional allocations for such schemes.

Non-plan Expenditure

47. The budget estimates for 2004-2005 show a net increase of Rs.16,218 crore in non-plan expenditure. The increase is mainly in interest payments and debt servicing (Rs.4,945 crore), defence (Rs.5,700 crore), grants and loans to State Governments (Rs.4,110 crore) and food subsidy (Rs.2,600 crore).

Revenue estimate and Fiscal deficit

48. Mr. Speaker, Sir, with these proposals I estimate total revenue receipts of the Centre at Rs.290,882 crore, the fiscal deficit at Rs.136,452 crore, which is 4.4 per cent of the estimated GDP and the revenue deficit at Rs.89,860 crore, which is 2.9 per cent of the estimated GDP.

V. CONCLUSION

49. Sir, I had the honour of being given the responsibility of the Ministry of Finance in July, 2002. I have served here for just about a year and a half. During this period it has been my privilege to see the Indian economy enter onto a sustained and robust growth path of around 7.5 to 8 per cent per year. This has been possible only because of the reforms pursued by the NDA, as well as by earlier Governments, of the contribution in this Ministry of my distinguished predecessor, Shri Yashwant Sinha, and above all, of the support and leadership provided by Prime Minister Vajpayee.

50. Under the stewardship of Shri Vajpayee, the NDA Government, since March 19, 1998, has not only successfully weathered the post-Pokhran economic sanctions; East Asian crisis; at least two major destructive cyclones; an unprecedented drought; the devastating Bhuj earthquake; two border stand-offs; the challenge of terrorism and insurgency; the gulf war; a global downturn; uncertainty in oil prices, all these and much else. Despite these multiple challenges, the Government, during this period, brought down the fiscal deficit to 4.8 per cent of GDP, the revenue deficit to 3.6 per cent, and contained annual average inflation at around 4.8 per cent. Our revenue collection in the period 1998-2004, has gone up by about 83 per cent, our capital markets are healthy, the UTI is a market leader again, our foreign exchange reserves have nearly quadrupled to the never ever achieved level of over \$100 billion, our GDP, in this period, has increased by almost 40 per cent, and to my belief, national contentment, national confidence, and our collective resolve for achieving even higher growth has now taken firm root.

51. Sir, I commend this interim budget to the House.

M. PRASAD, Jt. Secy. (FRBM)